श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं इस विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री ओ.टी. लेपचा (सिक्किम) : सर, मैं इस विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

Need to remove anomalies in the pay scales of Railway Engineers/Technical Supervisors in view of the recommendations of the Sixth Pay Commission

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : महोदय, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद देश के कई विभागों के कर्मचारी कई प्रकार की विसंगतियों के शिकार हुए हैं। रेलवे के तमाम इंजीनियर इसमें प्रमुख शिकार हैं। उनके इस विषय को मैं सदन के माध्यम से उजागर करके उनको राहत दिए जाने हेतु अनुरोध करता हूं।

Sir, I demand to fulfil the following grievances of railway engineers:

(1) Recognition of All India Railway Engineers Federation to discuss and resolve the problems of Railway Engineers/Technical supervisors as per the Khanna Committee Report.

(2) Grant of Grade Pay of Rs.4,800/- to JEs (Junior Engineers) at par with Nursing Sister and Rs.5,400/- to Section Engineers and Senior Section Engineers at par with Matron with standard designation of JE/AE, that is, JE (GP-4800) and AE (GP-5400).

(3) Group 'B' Gazetted status to all, that is, JEs (JE-II/JE-I) & AE (SE/SSE) as per DOPT Gazette Notification No.605 of 9th April, 2009.

(4) (a) AC-II entitlement to all JEs at par with other departments and as recommended by Sixth CPC.

(b) Inclusion of father & mother in privilege pass.

(5) Change of classification and provide designation also (since no financial implication is involved) under MACPS.

(6) Time-bound scales/promotions from JE to JA grade.

(7) Grant of special pay @ 30 per cent to all engineers and technocrats at par with scientists.

(8) Revision of rates of incentive bonus of engineers (JE-II, JE-I, SE & SSE) as per revised pay bands plus grade pay.

(9) (a) Incentives/arduous duty allowance @ 30 per cent to JEs, SEs, SSEs, CMS/DMS/CMT staff.

(b) Design/Planning/PCO allowance @ 30 per cent to drawing, design/IT (EDP) engineers.

10. Exemption of all allowances (DA & HRA) from income-tax.

11. No corporatisation of Railways.

I urge the Government to take immediate steps to consider and fulfil the above demands of the Railway engineers.

SHRI SAMAN PATHAK (West Bengal): Sir, I associate myself with the hon. Member.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I associate myself with the hon. Member.

SHRIMATI KUSUM RAI (Uttar Pradesh): Sir, I too associate myself with the hon. Member.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इस विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : सर, मैं भी अपने आपको इससे एसोसिएट करता हूं।

श्री रामचन्द्र खूंटिआ (उड़ीसा) : सर, मैं भी इस विषय से एसोसिएट करता हूं।

Concern over beggars being on the verge of death due to hunger and their inclination towards criminal activities because of soaring prices in country

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में पौने दो करोड़ भिखारियों की हालत दयनीय ही नहीं, बल्कि मरणीय हो रही है। दिल्ली में तो दिल्ली सरकार द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि Commonwealth Games से पहले दिल्ली भिखारी मुक्त होगी। क्या ये भिखारी ऊपर भेज दिए जाएंगे या इनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? जहां तक सवाल है सरकार बी.पी.एल. बना चुकी है, ए.पी.एल. बना चुकी है, लेकिन पता नहीं इन भिखारियों की जमात किस में आती है? मैं चिंतित इसलिए हूं कि पिछले दिनों मुंबई के वी.टी. स्टेशन पर तीन दिन तक दो भिक्षुक मृत पड़े रहे, वहीं जोगेश्वरी स्टेशन पर तीन दिन तक एक लाश पड़ी रही। साथ ही दिल्ली में अभी पिछले दिनों तीन मौतें भिखारियों की हुई हैं। जब मैंने पता किया तो पता चला कि शरीर से अशक्त इन भिखारियों को मुंह से भीख मांगने की ताकत भी नहीं बची थी। देश में अनेक समस्याएं होंगी, लेकिन इस ज्वलंत समस्या पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। इसका मुख्य कारण है कि 8 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष के लोगों की ज़िंदगी भीख के कटोरे से जुड़ी है। यह भी जानकारी है कि देश भर में इनके माध्यम से इन भिखारियों के बीच अपराध करने वाले लोग भी तैयार होते हैं। यहां तक जानकारी मिली है कि भिखारियों में जो थोड़े स्वस्थ पाए जाते हैं, उनके संबंध नामी अपराधियों से होते हैं और वे उनके लिए ट्रेन में काम करने लगते हैं। भारत में सभी ऐसे स्थानों पर जहां भिखारियों की संख्या ज्यादा होती है, वहां पर छानबीन होनी चाहिए। कारण यह है कि अगर छानबीन नहीं हुई तो इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग आगे चलकर देश के लिए घातक बनेंगे या भारत में कोई न कोई 26/11 जैसी बड़ी वारदात के लिए इनको माध्यम बनाएंगे। मुझे एक जानकारी और मिली है कि इनको महंगाई के कारण लोग अब भीख भी नहीं देते। कुछ भिखारियों का कहना था कि पहले एक दिन में 20-25-30 रुपए मिल जाते थे, अब वैसी स्थिति नहीं रही है।

मेरी सरकार से मांग है कि देश के सभी भिखारियों की छानबीन की जाए तथा जो अशक्त और अजीर्ण हैं, उनके लिए रैन बसेरा बनाया जाए या उनके बारे में कुछ सोचा जाए। मेरी आखिरी मांग है कि इसमें रेलवे और भारत की पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि नौनिहाल भिखारियों को नया जीवन मिलेगा तथा अशक्त और अजीर्ण भिखारियों को आवास एवं रोटी मिलेगी। धन्यवाद।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्ध करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, the whole House associates itself with this Special Mention.

Concern over drought conditions in several parts of Karnataka

SHRI K.B. SHANAPPA (Karnataka): Sir, the Karnataka State has received 460 mm of rainfall from 1st June to 31st July, 2009. This is 7 per cent more than the usual rainfall during this